नई शिक्षा नीति : नए शैक्षणिक युग की शुरुआत या मात्र औपचारिकता?

डॉ. हितेंद्र बारगल
डॉ. प्रियंका बारगल
विनोद कुमार पटेल

प्रस्तावना

वर्तमान में शिक्षा का स्तर बढ़ने के साथ-साथ उसका महत्त्व भी बढ़ता जा रहा है। आधुनिक युग में नित नए आविष्कार की नींव में हमारी शिक्षा ही है, जिसकी सहायता से ना केवल हम अपनी बल्कि समाज तथा देश की सीमाओं से परे विश्व की उन्नति कर सकते हैं, उसका कल्याण कर सकते हैं। जिस तरह से हर वस्तु में सुधार की गुंजाइश होती है, वैसे ही शिक्षा की गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी करने हेतु समय-समय पर हमारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार किए गए हैं। भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था का सूक्ष्म अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि भारत में अनौपचारिक तथा औपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षण संस्थाएँ देखने को मिलती थीं। बालक के जन्म के पश्चात, उसके थोड़ा बड़े होने पर उसके माता-पिता ही उसके मार्गदर्शक या शिक्षक हुआ करते थे तथा अपनी मातृभाषा तथा आसपास के वातावरण से उसका परिचय करवाते थे। माता पिता के अतिरिक्त उसके अन्य रिश्तेदार, पड़ोसी ये सभी मिलकर अनौपचारिक शिक्षण संस्था का निर्माण करते थे। औपचारिक शिक्षण संस्था में शिक्षा का माध्यम आश्रम एवं गुरुकुल हुआ करते थे, जिसमें विद्यार्थी को अपने घर से दूर, वन में गुरु के आश्रम में ही रहकर हर प्रकार की शिक्षा ग्रहण करनी होती थी। वैदिक काल में भारत में शिक्षा देने हेतु परिषद्, चरण तथा शाखा जैसी संस्था विकसित हो गईं थीं, किंतु व्यवस्थित शिक्षण संस्था का विकास, सार्वजनिक स्तर पर बौद्धों द्वारा ही शुरू किया गया।

शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास पर दृष्टिपात करने पर हम पाते हैं कि स्वतंत्रता के पूर्व अंग्रेजों के आने के पश्चात, अंग्रेजों द्वारा अपने फायदे के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई तथा भारतीयों में उन्हीं गुणों का विकास करवाया गया, जिससे कि वे अंग्रेजों की भक्ति कर सकें, उनका गुणगान कर सकें तथा उनके खिलाफ कोई भी कदम उठाने की हिम्मत ना कर सकें। उदाहरण के लिए वर्ष 1781 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा कोलकाता में मदरसा की स्थापना की गई थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य मुस्लिम शिक्षा का विकास एवं विस्तार करना था। वर्ष 1791 में जोनाथन डंकन द्वारा बनारस में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की गई, जिसका मुख्य ध्येय हिंदू शिक्षा का विकास एवं विस्तार करना था। वर्ष 1800 में लार्ड वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की (जिसे बाद में बंद कर दिया गया) इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों का शुरू से ही यह उद्देश्य रहा है कि हिंदू और मुस्लिम में फूट डालते हुए वह भारत पर किस प्रकार शासन कर सके, उसी स्तर का वातावरण वह भारत में बनाने के इच्छुक थे, तथा उसी तारतम्य में शिक्षा भारतीयों को प्रदान की जाती रही।

स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय शिक्षण व्यवस्था में सुधार करने हेतु हम मैकाले को याद कर सकते हैं, किंतु उसकी शिक्षण व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य अंग्रजों की गुलामी करने के लिए मात्र बाबू पैदा करना था।

शैक्षणिक युग की शुरुआत

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारे प्रमुख नेताओं ने देश के सर्वांगीण विकास के लिए, अपने स्तर पर शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किए। इस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयास डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 'राधाकृष्णन आयोग' का गठन करते हुए नवंबर 1948 में किया गया, जो विश्वविद्यालय शिक्षा के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ इस आयोग की सिफारिश पर ही सन् 1953 में 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' (U.G.C.) की स्थापना की गई, जिसे 1956 में संसद द्वारा स्वायत्तशासी संस्था का दर्जा प्रदान कर दिया गया। वर्तमान में भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं।

राधाकृष्णन आयोग के पश्चात 'कोठारी शिक्षा आयोग' (1964-66) का गठन किया गया। इस आयोग के माध्यम से

शिक्षा के सभी स्तरों तथा पक्षों का अध्ययन किया जाकर, शिक्षा से संबंधित सिद्धांत एवं नीतियाँ बनाई गईं इस आयोग द्वारा तत्कालीन शिक्षण पद्धतियों की आलोचना करते हुए, इन पद्धतियों को वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप लचीला बनाने पर जोर दिया गया। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही वर्ष 1968 में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' का सूत्रपात संभव हो सका।

शिक्षा के उत्तरोत्तर प्रयासों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, 1976 में शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया, पुनः 1986 में नवीन शिक्षा नीति लाई गई। इस नीति के द्वारा महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए शिक्षा के बराबर अवसर उपलब्ध करवाए जाने पर जोर दिया गया। 'इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय' (I.G.N.O.U.) इस नीति की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि रही, जिसने 'मुक्त विश्वविद्यालय का मार्ग प्रशस्त करते हुए, कामकाजी व्यक्तियों को भी अपनी शिक्षा का स्तर सुधारने तथा अधिक उन्नति के अवसर पाने का मौका दिया। समय के साथ-साथ इस नीति में भी परिवर्तन की आवश्यकता महसूस होने लगी, जिसका परिणाम 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन 1992' के रूप में सामने आया। व्यावहारिक धरातल पर अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था को परखें तो हम पाते हैं, कि हमारी शिक्षा प्रणाली केवल शिक्षित बेरोजगारों की लाइन बढ़ा रही थी। ऐसा शिक्षित व्यक्ति जो स्वरोजगार अपनाने की तुलना में, सरकार का मुँह ताकना ज्यादा पसंद करता है। अतः ऐसी शिक्षण व्यवस्था में आधारभूत परिवर्तन करने हेतु एवं व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु यह नीति लाई गई थी। पुनः ठहरे हुए जल में जिस प्रकार से गंदगी जमा होने लगती है, वहीं बहता हुआ जल अपने साथ सारी गंदगी को बहाकर, अपने पीछे स्वच्छ व निर्मल जल उपलब्ध करा देता है, उसी प्रकार परिवर्तित दशाओं के साथ अनुकूल सामंजस्य स्थापित करने एवं वैश्विक प्रतियोगिता हेतु भारतीय विद्यार्थियों को तैयार करने, जिससे वे शिक्षा की गुणवत्ता के साथ-साथ अपनी गुणवत्ता में भी सुधार कर सकें तथा नवाचार एवं अनुसंधान को बढ़ावा दे सकें, वैश्विक शिक्षण मानकों को अपनाने हेतु 'नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' लाई गई।

5 अगस्त 2020 को केंद्र सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई और इसी के साथ-साथ शिक्षाविदों के अतिरिक्त, आम जनता खासकर माता-पिता के बीच यह बहस का विषय हो गया है, कि इस एक विशेष शिक्षा नीति के आने के बाद शिक्षा जगत में किस तरह से बदलाव होंगे। स्कूली शिक्षा नीति वर्तमान के साथ-साथ भविष्य को किस प्रकार परिवर्तित करेगी तथा यह उच्च शिक्षा पर किस प्रकार प्रभाव डालेगी, यह भी बहस का विषय हो गया है, क्योंकि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति ऐतिहासिक है तथा 34 वर्षों बाद लाई गई है अतः शिक्षा नीति को लाने से पूर्व बहुत तैयारी की गई है, आमजन से राय माँगने के अतिरिक्त, अन्य राज्य सरकारों के साथ भी विचार विमर्श किया गया है। अतः यह कहा जा सकता है कि यह एक समावेशी नीति है, इस नीति के द्वारा विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के मध्य प्रतियोगिता बढ़ेगी जिसके परिणाम स्वरूप छोटी संस्थाओं को भी बढ़ावा मिलेगा तथा वे अपनी कुशलता में वृद्धि कर पाएँगी। इस नीति के कारण स्कूलों में भी वोकेशनल एजुकेशन को शामिल किया जा सकेगा। इसके साथ ही स्थानीय भाषा को भी शामिल किए जाने के कारण राज्यों के विद्यालय पहले से बेहतर प्रदर्शन कर पाएँगे। इस शिक्षा नीति द्वारा वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को खत्म करते हुए 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 व्यवस्था चलाई गई है। चूँकि विश्व, मानक स्तर पर परिवर्तित हो रहा है अतः हमें भी वैश्विक स्तर को प्राप्त करने तथा स्वयं का स्तर बढ़ाने हेतु शिक्षा व्यवस्था में सुधार जरूरी था। आज भारतीय विद्यार्थियों को विश्व स्तर का विद्यार्थी बनाने के साथ-साथ उन्हें अपनी भारतीय जड़ों से भी जोड़े रखना जरूरी है अतः यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई है जिसके चार प्रारूप हैं :

प्रथम प्रारूप : 1 से 3 साल का है
द्वितीय प्रारूप : 8 से 11 वर्ष के लिए है
तृतीय प्रारूप : 11 से 14 वर्ष के लिए है
चतुर्थ प्रारूप : 14 से 18 वर्ष के लिए है

इस शिक्षा नीति में सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद का 6% शिक्षा पर खर्च किया जाएगा।

चुनौतियाँ

किसी भी नए कार्य की शुरुआत करने से पहले कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लोगों की पारंपरिक सोच में बदलाव लाना अपने आप में एक महत्त्वपूर्ण ही नहीं बल्कि जोखिम भरा कार्य होता है, और भारत देश की बात की जाए, तो यहाँ हर कार्य की शुरुआत ही विवाद से होती है। जिस कार्य को राजनीति पक्ष सकारात्मक बताने की कोशिश करता है, उसी कार्य की नकारात्मकता की बातें विपक्ष द्वारा फैलाई जाती हैं। हाँ, यह बात और है कि विपक्ष के सत्ता में आ जाने पर वही नकारात्मक बातें पुनः सकारात्मक हो जाती है अर्थात् कई बार राजनीतिक दलों द्वारा भी अपने स्वार्थ पूर्ति हेतु योजना बनाई व क्रियान्वित की जाती हैं।

इसी तारतम्य में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भी लागू किया गया है, जिसके समक्ष भी कई चुनौतियाँ हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है–

पिछड़े बच्चों की पहचान

शिक्षा नीति कोई भी हो, उसका महत्त्वपूर्ण कार्य समाज के सभी वर्गों को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध करवाना होना चाहिए, सभी व्यक्ति अपने स्तर में बढ़ावा कर, अपनी प्रगति

कर सकें। ऐसे बच्चे जो मानसिक, शारीरिक व आर्थिक रूप से पिछड़े हों, उनकी पहचान सुनिश्चित करते हुए उन्हें भी विकास की मुख्यधारा में सम्मिलित करना एक चुनौती है।

शिक्षकों को प्रशिक्षित करना

नवीन शिक्षा नीति लागू करना ही पर्याप्त नहीं है, वरन इस नीति के क्रियान्वयन के लिए कार्मिक भी पर्याप्त शिक्षित एवं प्रशिक्षित होने चाहिए, जिससे कि वे सही रूप में तथा सही दिशा में नीति का क्रियान्वयन कर सकें तथा इस नीति को सही मायने में सफल सिद्ध करवाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर पाएँ और इस कार्य के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करना अपने आप में एक महत्त्वपूर्ण चुनौती है।

बेहतर आँकड़ों की उपलब्धता

किसी भी नीति के सुगम क्रियान्वयन के लिए तथा योजनाओं को कागजी कार्यवाही से आगे बढ़ाते हुए, व्यावहारिक धरातल पर लाने हेतु तथा योजनाओं को और अधिक सफल बनाने हेतु आँकड़ों की उपलब्धता आवश्यक है तथा यह आँकड़े फर्जी ना होकर सही एवं सटीक होना महत्त्वपूर्ण है, अन्यथा अर्थ का अनर्थ होने में देर नहीं लगती, अतः इन आँकड़ों का संग्रहण, सारणीयन तथा विश्लेषण अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है।

शिक्षकों की सही जगह नियुक्ति

शिक्षकों को पर्याप्त शिक्षण एवं प्रशिक्षण देने के पश्चात् उनकी नियुक्ति ऐसे स्थानों पर होनी चाहिए, जहाँ उनकी पर्याप्त आवश्यकता हो। प्रायः देखने में यह आता है, कि शिक्षक शहर में रहकर ही अध्यापन करना पसंद करते हैं, जिससे गाँवों की शिक्षण व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हो पाता अतः शिक्षकों को गाँवों में शिक्षा देने के लिए प्रोत्साहन देने के अतिरिक्त, उन्हें पर्याप्त वेतन, बोनस, आधारभूत सुविधाएँ देते हुए गाँव की ओर जाने तथा गाँव के बच्चों का विकास करने में सहायता देनी चाहिए।

शिक्षकों का सम्मान

वर्तमान में यह एक ज्वलंत समस्या है। एक तो वैसे भी कहीं-कहीं विद्यार्थियों के ऊपर केवल एक शिक्षक ही रहता है, वहीं आज की व्हाट्सएप जैसी तकनीकों, इसमें मीडिया भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, की भूमिकाओं के कारण आजकल के विद्यार्थी अपने आप को बहुत बड़ा समझने लग गए हैं, उन्हें लगता है कि शिक्षक का वेतन उनकी फीस द्वारा ही दिया जाता है, जिससे उनकी नजरों में शिक्षक के सम्मान में गिरावट आई है, जो भारतीय संस्कृति के बिलकुल अनुकूल नहीं कही जा सकती अतः शिक्षकों को उनका सही सम्मान, जिसके कि वे हकदार हैं, पुनः उपलब्ध करवाना अपने आप में एक चुनौती है।

शिक्षा की गुणवत्ता

भारत की शिक्षण पद्धति में क्रांतिकारी बदलाव की आवश्यकता है। विश्व की प्रमुख शिक्षण संस्थाओं की सूची में भारतीय शिक्षण संस्थाएँ बहुत ही निम्न स्तर पर आती हैं अतः विश्व सूची में अपना स्थान उच्च करने तथा देश की शिक्षा व्यवस्था को ऊँचा करने हेतु शिक्षण व्यवस्था में व्यापक रूप से सुधार की आवश्यकता अपने आप में एक महत्त्वपूर्ण चुनौती है।

इन सब चुनौतियों के अतिरिक्त शिक्षकों की, माता-पिता के अलावा विद्यार्थियों की जवाबदेही तय करना भी अपने आप में एक चुनौती भरा कार्य है। हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त गैर हिंदी भाषा वाले क्षेत्रों में स्थानीय भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाना भी एक चुनौती पेश कर रहा है।

निष्कर्ष

निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि वर्तमान सरकार द्वारा 'सबका साथ सबका विकास' के नारे को क्रियान्वित रूप देते हुए जिस प्रकार से सभी क्षेत्रों के लिए आवश्यक, महत्त्वपूर्ण एवं नींव 'शिक्षा' में जिस बदलाव को लाया गया है, उसे भले ही अपना सही स्वरूप पाने में समय लगे, पर वह दिन दूर नहीं, जब एक आम भारतीय विद्यार्थी भी वैश्विक परिदृश्य में अपनी महत्त्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज करा पाएगा तथा ना केवल भारत, बल्कि विश्व में भी नवाचार एवं अनुसंधान को बल देते हुए एक सशक्त व्यक्तित्व का निर्माण कर सकेगा। अगर हम सभी मिलकर इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को साकार कर पाए, तो वह दिन दूर नहीं जब भारत पुनः 'विश्वगुरु' का अपना खोया हुआ मान सम्मान प्राप्त कर 'विश्व विजेता' बनकर दैदीप्यमान हो सकेगा।

संदर्भ सूची

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार। अग्रवाल, पी. (2018)
2. भारतीय उच्च शिक्षा के पाँच दशक : फिलिप जी अल्ट्बॅच के निबंधों का संकलन, सेज पब्लिशिंग इंडिया।
3. रहीस, एस. (2010), आधुनिक भारतः भारत में ब्रिटिश राज का विस्तार (1707-1857), पीयर्सन एजुकेशन इंडिया।
4. दुबे, एस.एस. (2000) शिक्षा समाज और भविष्य, राजकमल प्रकाशन।
5. डॉ. मंजू शर्मा एवं श्रीमती उषा जैन (2020), शिक्षा नीति 2019 प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा। निबंध माला, 12(3), 1070-1079।